

# ब्याज टुडे

## केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम' में संशोधन को मंजूरी दी

भारत सरकार 2022 से विविध उपायों के माध्यम से पूरे देश में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) को लागू कर रही है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पशु स्वास्थ्य के समक्ष जोखिम को कम करना है।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के बारे में

► उद्देश्य: प्राथमिक रूप से पशुधन एवं कुक्कुट प्रजातियों के विविध रोगों के लिए रोग-निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से पशु स्वास्थ्य में सुधार करना।

⊕ इसमें क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है।

► इसमें तीन घटक शामिल हैं: राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (LH&DC) और पशु औषधि।

⊕ पशु औषधि इस योजना में जोड़ा गया नया घटक है। इसका उद्देश्य पी.एम.-किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना है।

⊕ LH&DC के भी तीन उप-घटक हैं:

◆ गंभीर पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (CADCP): किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दो गंभीर बीमारियों को नियंत्रित करने और उन्मूलन के लिए कवर करने का प्रस्ताव है। ये दो बीमारियां हैं- पेस्ट डेस पेटिटस रुमिनेंट्स व स्वाइन फीवर।

◆ मौजूदा पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना व सुदृढीकरण- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई (ESVHD-MVU): यह पशुधन स्वास्थ्य देखभाल की घर-घर पहुंच की सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है।

◆ पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यो को सहायता (ASCAD): राज्य-प्राथमिकता वाले विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक पशु रोगों को लक्षित करना, जिसमें लम्पी स्किन डिजीज (LSD) भी शामिल है।

सरकार द्वारा पशुधन संवर्धन के लिए उठाए गए अन्य कदम

► राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): कुक्कुट, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा, इस मिशन में पशुओं के आहार एवं चारे के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाता है।

► पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): दुग्ध और मांस प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधता बढ़ाने में मदद करना।

► राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): गोवंश की उत्पादकता बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

## RBI ने आर्थिक संवृद्धि को गति देने के लिए बैंकों में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की लिक्विडिटी बढ़ाने की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यह कार्य ओपन मार्केट ऑपरेशन्स के तहत निम्नलिखित दो पहलों के जरिए पूरा करेगा:

► सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद, और

► अमेरिकी डॉलर/ भारतीय रुपया (USD/INR) बाय/ सेल स्वैप नीलामी।

ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) के बारे में:

► इसके तहत, RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद या बिक्री करता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर बढ़ती या घटती है।

► खुले बाजार में G-Secs की खरीद हाई पावर्ड मनी (H) की आपूर्ति बढ़ाती है, जबकि उनकी बिक्री से हाई पावर्ड मनी की समान मात्रा में आपूर्ति कम हो जाती है।

⊕ हाई पावर्ड मनी वास्तव में वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा भंडार और जनता के पास मुद्रा (नोट और सिक्के) का योग है।

अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया (USD/INR) स्वैप नीलामी के बारे में:

► इसके तहत, कोई बैंक RBI को अमेरिकी डॉलर बेचता है और स्वैप अवधि की समाप्ति पर समान मात्रा में डॉलर वापस खरीदने के लिए सहमत होता है।

► यह कार्य नीलामी के माध्यम से किया जाता है। इसमें प्रत्येक बैंक अपनी स्वैप दर (फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट) का उल्लेख करता है, और सबसे कम दर की बोली लगाने वाले बैंक को प्राथमिकता दी जाती है।

बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है?

► बैंकिंग प्रणाली में नवंबर 2024 से ही लिक्विडिटी की कमी पर चिंता जताई जा रही है। लिक्विडिटी की कमी की निम्नलिखित वजहें हैं:

⊕ करों का भुगतान करने के लिए बैंकों से धनराशि निकलना;

⊕ बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी में बिकवाली,

⊕ विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप, आदि।

► बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाने के कई फायदे हैं। इनमें कुछ मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं:

⊕ ब्याज दरों में कटौती का लाभ आम कर्जदारों को भी प्राप्त होता है,

⊕ RBI की मौद्रिक नीति का सही से क्रियान्वयन हो पाता है,

⊕ आर्थिक संवृद्धि को गति मिलती है आदि।



अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ाने के अन्य उपाय

► मात्रात्मक उपाय (Quantitative Tools): तरलता समायोजन सुविधा (रेपो एवं रिवर्स रेपो), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), बैंक दर, आदि।

► गुणात्मक उपाय (Qualitative Tools): क्रेडिट राशनिंग, नैतिक अनुरोध (Moral Suasion), सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल (SCC), मार्जिन आवश्यकता, आदि।

## नीति आयोग ने राष्ट्रीय सुरक्षा में क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका को उजागर किया

क्वांटम कंप्यूटिंग में निम्नलिखित प्रगति कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को पुनर्परिभाषित कर रही है:

- लंबे समय तक बने रहने वाला क्यूबिट कोहेरेंस, जो क्यूबिट को स्थिरता प्रदान करता है;
- बेहतर क्यूबिट नियंत्रण और विश्वसनीयता, जो सटीकता को बढ़ाती है; तथा
- लुटि सुधार में प्रगति (उदाहरण के लिए सेल्फ-चेकिंग प्रणाली के साथ गूगल ने विलो चिप लॉन्च की है)।
  - ⊕ हाल ही में, नीति आयोग ने नीति फ्रंटियर टेक हब की स्थापना की है। यह भारत को फ्रंटियर टेक में अग्रणी बनाने के लिए एक एक्शन टैक के रूप में कार्य करेगा।
  - ◆ फ्रंटियर टेक अत्याधुनिक और नई उभरती तकनीकों को कहते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्वांटम कंप्यूटिंग की भूमिका

- क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा: उदाहरण के लिए, फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक-की एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं। इससे इंटरनेट सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग और संचार प्रणाली असुरक्षित हो सकती हैं।
- खुफिया जानकारी एकत्र करना: जटिल और विशाल डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता से सिग्नल इंटेलेजेंस में वृद्धि हो सकती है। इससे अत्यधिक प्रभावशाली इंटरसेप्शन और काउंटर-इंटेलेजेंस संचालन संभव हो सकते हैं।
- सैन्य क्षेत्र में उपयोग: क्वांटम एल्गोरिदम लॉजिस्टिक्स, संसाधन आवंटन तथा युद्धक्षेत्र रणनीति को और बेहतर एवं सटीक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम-आधारित AI स्वचालित सैन्य ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम्स के संचालन को बेहतर बना सकते हैं।
- क्वांटम भू-राजनीति: क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रिम सफलताएं और प्रतिस्पर्धा भविष्य की वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता को निर्धारित करेगी।



मुख्य सिफारिशें

- निरंतर निगरानी और क्रिप्टोग्राफिक इंटेलेजेंस: वैश्विक स्तर पर क्वांटम के क्षेत्र में प्रगति पर नज़र रखने और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रणालियों में खामियों का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना करनी चाहिए।
- पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) ट्रांजिशन प्लान: इसमें जोखिम के मामले में प्राथमिकता-आधारित ट्रांजिशन और रोडमैप शामिल होना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी पहुंच समझौते: इस क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं इसका विस्तार करने वाले तौर-तरीकों को तेजी से अपनाने के लिए द्विपक्षीय साझेदारियों की जानी चाहिए।

## गुजरात के धोलेरा में भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

यह समझौता इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL), और टाटा सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (TSMPL) के बीच हस्ताक्षरित किया गया है।

- इसे 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की सेमीकंडक्टर परियोजना को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ड्स प्रति माह (WSPM) होगी।
- भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए इस परियोजना के लिए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत समान आधार पर 50% वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है।
  - ⊕ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक विशेष और स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग है।

सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में

- उद्देश्य: सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- वित्तीय परिचय: 76000 करोड़ रुपये।
- कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही योजनाएं:
  - ⊕ भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना;
  - ⊕ भारत में डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना
  - ⊕ भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/ सेंसर फैब/ डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP)/ OSAT सुविधाएं स्थापित करने के लिए संशोधित योजना;
  - ⊕ डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन (DLI) योजना आदि।



अन्य पहलें

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना: इसका उद्देश्य घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में आने वाली चुनौतियों को कम करना है।
- व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना: इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करना है।
- चिप्स टू स्टार्ट-अप (C2S) कार्यक्रम: इसका उद्देश्य देश में एक सशक्त फैबलेस चिप डिजाइन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए उद्योग-अनुकूल श्रमबल तैयार करना है।

## सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में कैम्पा (CAMP) फंड के दुरुपयोग पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से CAG रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण कोष (कैम्पा फंड) के दुरुपयोग के आरोपों पर जवाब मांगा है।

### ▶ प्रतिपूरक वनरोपण के बारे में

⊕ यदि वन भूमि का गैर-वन्य उद्देश्यों के लिए 'उपयोग' किया जाता है, तो इसके ही समान भू-क्षेत्र पर वनरोपण का प्रयास करना अनिवार्य है। गैर-वन्य उद्देश्यों में औद्योगिक या अवसंरचना का विकास करना आदि शामिल है।

- ◆ प्रतिपूरक वनरोपण में गैर-वन भूमि या निम्नीकृत वन भूमि की पहचान करना, फंड की व्यवस्था करना, फंड का उपयोग करना और निगरानी तंत शामिल होता है।

### ▶ कानूनी प्रावधान

⊕ वन (संरक्षण) अधिनियम 1980: जब भी वन भूमि का गैर-वन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना हो तो समान मात्रा में गैर-वन भू-क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनरोपण और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था करनी होगी।

⊕ प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016:

- ◆ इसमें राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना, प्रबंधन एवं उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है।
- ◆ ये निधियां व्यपगत नहीं होती और इन पर ब्याज मिलता है। राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि भारत के लोक लेखा के अधीन होती है।
- ◆ प्रतिपूरक वनरोपण निधि के प्रबंधन और उपयोग के लिए राष्ट्रीय कैम्पा एवं राज्य कैम्पा के गठन का प्रावधान किया गया है।
- ◆ प्रतिपूरक शुल्क राष्ट्रीय एवं राज्य निधियों में 10:90 के अनुपात में बांटा जाता है।



## अन्य सुर्खियां



### पार्थक्यवाद (Isolationism)

कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा अपनाई जा रही नीतियां पार्थक्यवाद का संकेत देती हैं।

पार्थक्यवाद के बारे में

- ▶ यह एक प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत या व्यवहार है। इसमें कोई राष्ट्र केवल अपने आंतरिक मामले में रुचि रखता है और अन्य देशों के मामले में राजनीतिक या आर्थिक रूप से उलझने से बचता है।
- ▶ इस सिद्धांत ने समय-समय पर अमेरिकी विदेश नीति को दिशा दी है। इस नीति या सिद्धांत को तब अपनाया जाता है, जब अधिक खर्चों या जोखिम भरे अंतर्राष्ट्रीय मामले में संसाधनों को लगाने के बाद भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विफलता हाथ लगती है।
- ▶ नीति के लाभ: धरलू मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाने लगता है, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से बचा जाता है आदि।
- ▶ नुकसान: वैश्विक मामलों से निपटने में अधिक प्रभावी नहीं होना, अक्सर आर्थिक संवृद्धि को कम करती है।



### माजुली द्वीप

असम के माजुली नदी द्वीप पर बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की वजह से इस क्षेत्र में कृषि पर निर्भर लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है।

माजुली द्वीप के बारे में

- ▶ अवस्थिति: असम में ब्रह्मपुल नदी में।
- ▶ यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी-द्वीप है।
- ▶ यह भारत में जिले का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला द्वीप है।
- ▶ द्वीप का निर्माण: इस द्वीप का निर्माण दक्षिण में ब्रह्मपुल नदी और उत्तर में सुबनसिरी नदी में मिलने वाली खेरकुटिया जूती से हुआ है।
- ⊕ खेरकुटिया जूती, ब्रह्मपुल नदी की एक शाखा है।
- ▶ इसका निर्माण ब्रह्मपुल नदी और इसकी सहायक नदियों, मुख्य रूप से लोहित द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है।
- ▶ यह असमिया नव-वैष्णव संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर वैष्णव 'सल' की स्थापना शंकरदेव द्वारा की गई थी।



### पर्वतमाला परियोजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी।

पर्वतमाला परियोजना (2023) के बारे में

- ▶ उद्देश्य: पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- ▶ नोडल मंत्रालय: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)।
- ▶ कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (NHLML)।
- ⊕ यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है।
- ▶ इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार परियोजना लागत का लगभग 60% सहायता प्रदान करेगी।
- ▶ रोपवे के लाभ: लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है, पर्यावरण-अनुकूल कनेक्टिविटी मिलती है, दुर्गम इलाकों के लिए आदर्श कनेक्टिविटी है आदि।



### ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ)

सुप्रीम कोर्ट ने वन अनुसंधान संस्थान (FRI) को ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ) में वृक्षों की गणना करने का निर्देश दिया।

ताज ट्रैपेजियम जोन (TTZ) के बारे में

- ▶ ताज ट्रैपेजियम जोन ताजमहल स्मारक के चारों ओर लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर का अधिसूचित क्षेत्र है। इस अधिसूचित क्षेत्र का उद्देश्य प्रदूषण से ताजमहल को बचाने से बचाना है।
- ▶ इस जोन में यूनेस्को की सूची में शामिल तीन विश्व धरोहर स्मारक (ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी) शामिल हैं।
- ▶ 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ में स्थित उद्योगों में कोयला/ कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन उद्योगों को या तो कोयला/ कोक की जगह प्राकृतिक गैस अपनाने या फिर कहीं और स्थापित करने का आदेश दिया गया था।
- ▶ केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत ताज ट्रैपेजियम जोन (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया है।
- ▶ TTZ में क्षेत्रों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट जोन में श्रेणीबद्ध किया गया है।



### एक्टिवेटेड कार्बन

एक्टिवेटेड कार्बन उद्योग चुनौतियों का सामना करते हुए अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

➤ इसके समक्ष निम्नलिखित मुख्य चुनौतियां हैं:

- ⊕ बढ़ती उत्पादन लागत,
- ⊕ नारियल के खोल (coconut shell) की घटती उपलब्धता,
- ⊕ वैश्विक स्तर पर स्वर्ण उद्योग में एक्टिवेटेड कार्बन की बढ़ती मांग।

एक्टिवेटेड कार्बन के बारे में:

- इसे एक्टिवेटेड चारकोल/ कोयला या एक्टिव कार्बन भी कहा जाता है।
- उत्पादन: कार्बन की उच्च मात्रा वाले पर्यावरणीय अपशिष्टों से।
- विशेषताएं:
  - ⊕ उच्च पृष्ठीय क्षेत्रफल (High surface area);
  - ⊕ छिद्रित संरचना (माइक्रो, मेसो और मैक्रो),
  - ⊕ उच्च पृष्ठीय अभिक्रिया।
- उपयोग:
  - ⊕ जल को शुद्ध करने, क्लोरिन को हटाने और दुर्गंध दूर करने में;
  - ⊕ खाद्य उत्पादों, कॉस्मेटोलॉजी और ऑटोमोबाइल उद्योग में किफायती अधिशोषक (adsorbent) के रूप में;
  - ⊕ बहुमूल्य धातुओं, विशेष रूप से सोने की रिकवरी में।



### LCA तेजस

हाल ही में, DRDO ने हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (ILSS) के उच्च ऊंचाई वाले परीक्षण किए।

➤ ILSS एक उन्नत प्रणाली है, जो उड़ान के दौरान पायलटों के लिए सांस लेने योग्य ऑक्सीजन उत्पन्न और नियंत्रित करती है। इस प्रणाली के इस्तेमाल से पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।

LCA तेजस के बारे में

- यह एक भारतीय सिंगल-इंजन 4.5-पीढ़ी का बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है।
- इसे DRDO की वैमानिकी विकास एजेंसी ने डिजाइन और विकसित किया है।
- इसके तीन उत्पादन संस्करण:
  - ⊕ तेजस मार्क 1,
  - ⊕ मार्क 1A, और
  - ⊕ तेजस ट्रेनर/ लाइट अटैक एयरक्राफ्ट।



### चक्रीय अर्थव्यवस्था पर जयपुर घोषणा-पत्र

एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से 'जयपुर घोषणा-पत्र' अपनाने के साथ संपन्न हुआ।

जयपुर घोषणा-पत्र (2025-2035) की मुख्य विशेषताएं

- प्रकृति: यह एक स्वैच्छिक घोषणा-पत्र है।
- यह घोषणा-पत्र संसाधन दक्षता और सतत सामग्री उपभोग पर बल देता है। साथ ही, इसमें अनौपचारिक क्षेत्रकों, लैंगिक मुद्दों एवं श्रम संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया गया है।
- इसमें एक वैश्विक गठबंधन C-3 (सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी) के रूप में एक सहयोगी ज्ञान मंच स्थापित करने पर भी सहमति बनी है।
- इसमें कार्यान्वयन के साधन, साझेदारी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त-पोषण तंत्र और अनुसंधान एवं विकास का प्रावधान किया गया है।
- घोषणा-पत्र में 3R (रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल) तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के एकीकरण का आह्वान किया गया है।



### प्लैटिनम

हाल ही में, भारत ने व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लैटिनम मिश्र धातुओं पर आयात प्रतिबंध लगाए।

प्लैटिनम (Pt) के बारे में

- यह एक चमकदार, चांदी के समान धातु है। यह सोने और चांदी दोनों की तुलना में अधिक दुर्लभ है।
- यह सबसे स्थिर धातुओं में से एक है और उच्च तापमान पर भी संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी है।
- यह जलोद्द नक्षेपों में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है।
- अधिकांश व्यावसायिक रूप से उत्पादित प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। अफ्रीका में यह धातु कूपेराइट (प्लैटिनम सल्फाइड) खनिज के रूप में मिलती है।
- कुछ प्लैटिनम तांबा और निकेल के शोधन के उप-उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है।
- उपयोग:
  - ⊕ रासायनिक उद्योग में नाइट्रिक एसिड, सिलिकॉन और बेंजीन के उत्पादन के लिए उत्प्रेरक के रूप में।
  - ⊕ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में कंप्यूटर हार्ड डिस्क और थर्मोकपल्स में।
  - ⊕ कैसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दवा के रूप में।

## सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व



### बिजयानंद पटनायक (5 मार्च 1916-17 अप्रैल 1997)

प्रधान मंत्री ने ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजयानंद पटनायक को उनकी जयंती पर याद किया।

बिजयानंद पटनायक के बारे में

➤ वे आधुनिक ओडिशा के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। उन्हें बीजू पटनायक के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्य योगदान:

- उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में हिस्सा लिया था।
- वे भारतीय वायु सेना में पायलट थे।
- 1961 में वे ओडिशा के मुख्यमंत्री बने थे।
- उन्होंने कलिंग फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार करना था। उन्होंने यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले कलिंग पुरस्कार की भी स्थापना की थी।
- उपलब्धियां: इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने उन्हें भूमि पुत्र (सन ऑफ सॉयल) की उपाधि से सम्मानित किया था।
- मुख्य मूल्य: देशभक्ति, नेतृत्व, साहस आदि।

